Shortage of teachers in Kendriya Vidyalayas

*277. SHRI DIGVIJAY SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state.

(a) whether it is a fact that there has been an acute shortage of teachers in a large number of Kendriya Vidyalayas for the last three years;

(b) whether it is also a fact that in many Kendriya Vidyalayas this shortage is to the tune of 50 per cent to 75 per cent of the sanctioned staff strength; if so, the number of such Vidyalayas; and

(c) the steps taken by Kendriya Vidyalaya Sangathan to fill up the vacant posts?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Out of a total of 31036 sanctioned posts of teachers, 7996 posts were vacant as in April, 1992.

(b) A statement giving the list of schools where vacant posts are more than 50% is laid on the Table of the House. (*see* below)

(c) The Sangathan has already selected a panel of 1100 number of teachers for filling up back-log of reserved vacancies. Besides, in response to advertisement issued in July, 1992, about 3.6 Lakhs applications have been received by Kendriya Vidyalaya Sangathan and the selection process is under way. A substantial number of vacancies will be filled up as a result of these measures.

Statement

List of Kendriya Vidyalayas where more than 50% posts vacant

STATE	STATIONS
Assam	1. Bargolai
	2. Haflong SSB
	3. Lumding
	4. Namrup
	5. Bongaigaon
Gujarat	1. Chandkheda
	2. Mora
	3. Viramgaon
	4. Bhuj No. 1 AFS
	5. Bhuj No. 2 Army
	6. Naliya
	7. Porbandar
Nagaland	1. Tuli
Madhya Pradesh	1. Akaltara
	2. Chandarmetta
	3. Chirimiri
	4. Jamuna Colliery
	5. Nowrojabad
	6. Singrauli
	7. Vijayapur

कृषि-वृद्धि

*278. **श्री वीरेन जे० शाह:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अगस्त, 1992 के "आब्जर्वर" में "रीजनल इम्बेलेंसिज वाइडनिंग इन एग्रीकल्चर ग्रोथ" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में न्यूनतम औसत कृषि उत्पादन और अधिकतम औसत कृषि उत्पादन का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान निरन्तर बढ़ती हुई उत्पादन लागत के कारण अधिकतम उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादकों ने अपने कृषि उत्पादन के स्वरूप को बदल दिया है और अब वे खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल आदि के बजाय नकदी फसलें उगा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने क्षेत्र में भूमि के उपयोग में परिवर्तन किया गया है और क्या इसके परिणामस्वरूप देश में खाद्यान्न के उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) जी, हां।

(ख) 1990-91 की प्रमुख फसलों का प्रति हेक्टेयर अधिकतम और न्यूनतम औसत उत्पादन (उपज) को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ग) फसल उत्पादन के स्वरूप में ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे कि यह जान पड़े कि हाल के वर्षों में उच्च उत्पादकता वाले

राज्यों में चावल, गेहूं आदि के क्षेत्रों में अन्य नकदी फसलें उगायी जा रही हैं। इन क्षेत्रों के कुछ ही भागों में अब नकदी फसलें पैदा की जाने लगी हैं।

(घ) और (ङ) खाद्यान्न क्षेत्रों में मामूली कमी होने के बावजूद उत्पादकता की उच्च वृद्धि दर के कारण खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि होने की संभावना है।

विवरण

1990-91 की प्रमुख फसलों का प्रति हेक्टेयर अधिकतम व न्यूनतम औसत उत्पादन (उपज)

फसल	अधिकतम		न्यूनतम	
	उपज	राज्य	उपज	राज्य
1	2	3	4	5
चावल	3229	पंजाब	1121	मध्य प्रदेश
गेहूं	3715	पंजाब	1052	महाराष्ट्र
ज्वार	1014	तमिलनाडु	444	गुजरात
बाजरा	1115	उत्तर प्रदेश	513	राजस्थान
मक्का	2525	कर्नाटक	1320	उत्तर प्रदेश
तूर	1234	उत्तर प्रदेश	418	महाराष्ट्र
चना	879	उत्तर प्रदेश	532	महाराष्ट्र
कुल दलहन	912	उत्तर प्रदेश	401	कर्नाटक
कुल खाद्यान्न	3390	पंजाब	846	महाराष्ट्र
तोरिया व सरसों	1338	हरियाणा	851	राजस्थान
मूंगफली	1409	उड़ीसा	619	गुजरात
कुल तिलहन	1327	हरियाणा	525	कर्नाटक
कपास	463	पंजाब	111	मध्य प्रदेश
जूट व मेस्ता	1959	पश्चिम बंगाल	1306	बिहार
गन्ना	100817	तमिलनाडु	52490	बिहार

Allocation for Irrigation Projects

*279. SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the amount allocated for Irrigation Projects in the country during the current year; and

(b) the funds earmarked for rural water supply schemes during the years 1992-93 and 1993-94?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V.C. SHUKLA): (a) The following amount has been allocated for Irrigation Projects for States & Union Territories in the country during the current year in Annual Plan 1992-93:

(i) Major & Medium	Rs. 3097.56 crores
(ii) Minor Irrigation	Rs. 1037.50 crores
Total	Rs. 4135.06 crores

(b) The funds earmarked for various rural water supply schemes in 1992-93 are as under:

(i) Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission in Central Sector Plan	Rs. 460 crores
(ii) State/UT Plans	Rs. 810 crores
Total	Rs. 1270 crores

The amount for 1993-94 is yet to be decided.